नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 212
दि. 06.05.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

थाली में मिला 'जहर': सूरत में नकली पनीर के दो साल लंबे खेल का भंडाफोड़, खाद्य सुरक्षा पर बड़ा सवाल

सूरत। शहर के पांडेसरा इलाके में सामने आए एक बड़े खुलासे ने पूरे देश में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस पनीर को आमतौर पर प्रोटीन और सेहत का स्रोत माना जाता है, वही पनीर कई घरों और होटलों की थाली में 'छिपा खतरा' बनकर पहुंच रहा था। सूरत में की गई संयुक्त कार्रवाई में यह खुलासा हुआ कि एक अवैध फैक्ट्री पिछले लगभग दो वर्षों से नकली और मिलावटी पनीर का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रही थी, जिसे शहर के अलग-अलग हिस्सों में सप्लाई किया जा रहा था।

यह कार्रवाई शहर की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई। छापेमारी के दौरान जो दृश्य सामने आया, वह न केवल चौंकाने वाला था बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से बेहद चिंताजनक भी था। फैक्ट्री के अंदर पनीर बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह अस्वच्छ और मानकों के खिलाफ पाई गई। जहां सामान्य रूप से दूध को जमाने के लिए सुरक्षित और खाद्य-ग्रेड सामग्री का उपयोग किया जाता है, वहीं यहां औद्योगिक एसिड जैसे खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल किया जा रहा था।

जांच में सामने आया कि दूध को फाड़ने के लिए इंडस्ट्रियल ग्रेड एसिड का उपयोग किया जा रहा था, जो खाने योग्य नहीं बल्कि केवल औद्योगिक उपयोग के लिए होता है। इसके साथ ही पामोलिन तेल और अन्य सस्ते रसायनों का मिश्रण करके पनीर जैसा दिखने वाला पदार्थ तैयार किया जा रहा था। यह उत्पाद दिखने और स्वाद में असली पनीर जैसा लगता था, जिससे आम उपभोक्ता आसानी से धोखा खा जाते थे।

छापेमारी के दौरान लगभग 1400 किलोग्राम से अधिक लूज पनीर बरामद किया गया, जिसे बेहद गंदे और अस्वच्छ माहौल में रखा गया था। इसके अलावा बड़ी मात्रा में पामोलिन तेल, केमिकल ड्रम और पनीर निर्माण में इस्तेमाल

होने वाली मशीनरी भी जब्त की गई। जब्त सामग्री की कुल कीमत लाखों रुपये में आंकी गई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यह कोई छोटा स्तर का अवैध कारोबार नहीं था, बल्कि एक संगठित सप्लाई नेटवर्क के तहत चल रहा बड़ा रैकेट था।

लैब परीक्षण में यह पनीर पूरी तरह 'सब-स्टैंडर्ड' पाया गया, यानी यह किसी भी खाद्य गुणवत्ता मानक पर खरा नहीं उतरता था। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे उत्पादों का सेवन मानव शरीर के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। लंबे समय तक इनके उपयोग से फूड पॉइजनिंग, आंतों में संक्रमण, लीवर और किडनी पर गंभीर असर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों ने यह भी आशंका जताई है कि लगातार सेवन की स्थिति में यह किडनी फेल्योर जैसी जानलेवा स्थितियों तक पहुंच सकता है।

जांच में यह भी सामने आया कि यह अवैध कारोबार लगभग दो वर्षों से चल रहा था और रोजाना सैकड़ों किलो नकली पनीर तैयार कर शहर के विभिन्न इलाकों में सप्लाई किया जा रहा था। यह पनीर छोटे-बड़े होटल, ढाबों और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं तक पहुंचता था, जिससे अनजाने में हजारों लोग इसका सेवन कर रहे थे।

सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि इस यूनिट का लाइसेंस किसी अन्य राज्य से प्राप्त किया गया था, जबकि उत्पादन और वितरण पूरी तरह सूरत में हो रहा था। यह नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें लाइसेंसिंग और संचालन के बीच भारी अनियमितता पाई गई।

मुख्य आरोपी के खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के मामलों में केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संगठित सप्लाई चेन काम कर रही होती है, जिसमें कई स्तरों पर लोग शामिल हो सकते हैं। इस घटना के बाद खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों पर भी दोबारा ध्यान दिया जा रहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी वेजिटेबल फैट या स्टार्च आधारित उत्पाद को 'पनीर' नाम से बेचना अवैध माना जाएगा। ऐसे उत्पादों पर 'एनालॉग' लेबल लगाना अनिवार्य होगा, ताकि उपभोक्ता भ्रमित न हों।

इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि इतने लंबे समय तक यह अवैध कारोबार कैसे चलता रहा और निगरानी व्यवस्था को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। यह केवल एक फैक्ट्री का मामला नहीं, बल्कि खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में मौजूद संभावित कमजोरियों की ओर भी इशारा करता है।

फिलहाल प्रशासन सतर्क हो गया है और शहर में अन्य संभावित यूनिट्स की जांच भी शुरू कर दी गई है। लेकिन इस घटना ने आम उपभोक्ता को भी झकझोर दिया है कि रोजमर्रा की थाली में वह जो भोजन खा रहा है, वह कितना सुरक्षित है और कितना नहीं। यह मामला अब केवल एक अपराध नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा एक गंभीर चेतावनी संकेत बन चुका है, जो पूरे सिस्टम को आत्ममंथन के लिए मजबूर कर रहा है।

बंगाल और असम में सत्ता गठन की तैयारी तेज भाजपा ने वरिष्ठ नेताओं को सौंपी अहम जिम्मेदारी

नई दिल्ली। देश के दो महत्वपूर्ण राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया को गति देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ी रणनीतिक पहल शुरू कर दी है। पार्टी नेतृत्व ने पश्चिम बंगाल और असम में विधायक दल के नए नेता के चयन के लिए वरिष्ठ केंद्रीय नेताओं को केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि पार्टी अब जल्द ही सरकार गठन की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाने जा रही है।

इस प्रक्रिया के तहत पश्चिम बंगाल जैसे राजनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील राज्य की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई है। उन्हें केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर पार्टी ने यह संकेत दिया है कि राज्य में विधायक दल के नेता का चयन पूरी गंभीरता और रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ किया जाएगा। बंगाल लंबे समय से भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र रहा है, जहां हर निर्णय का असर राज्य की राजनीतिक दिशा पर सीधे दिखाई देता है।

अमित शाह के साथ इस प्रक्रिया में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को सह-पर्यवेक्षक बनाया गया है। यह संयोजन केवल औपचारिक नियुक्ति नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक संतुलित रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व और क्षेत्रीय

अनुभव दोनों का समन्वय किया गया है। पार्टी की कोशिश है कि पश्चिम बंगाल में विधायक दल का नेता ऐसा चुना जाए जो संगठन को एकजुट रख सके और विधानसभा में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा सके या संभावित सत्ता संरचना को मजबूती दे सके।

दूसरी ओर, पूर्वोत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक असम में भी भाजपा ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। यहां विधायक दल के नेता के चयन की जिम्मेदारी पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को दी गई है। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सह-पर्यवेक्षक बनाया गया है। यह टीम असम में विधायकों के साथ सीधी बातचीत कर अंतिम निर्णय लेगी।

असम की राजनीतिक स्थिति भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में भाजपा की रणनीतिक पकड़ का केंद्र रहा है। यहां विधायक दल के नेता का चयन केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करने वाला कदम माना जा रहा है। जेपी नड्डा के नेतृत्व में होने वाली यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि पार्टी के भीतर किसी भी प्रकार की गुटबाजी न पनपे और सभी विधायक एक साझा नेतृत्व के तहत काम करें।

भाजपा की इस पूरी रणनीति का उद्देश्य संगठन में पारदर्शिता और सामूहिक सहमति को प्राथमिकता देना बताया जा रहा है। विधायक दल के नेता का चयन आमतौर पर पार्टी के भीतर सर्वसम्मति और परामर्श के आधार पर किया जाता है, लेकिन बड़े और संवेदनशील राज्यों में यह प्रक्रिया और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय पूरी तरह संतुलित और संगठनात्मक हितों के अनुरूप हो।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की नियुक्तियां केवल औपचारिकता नहीं होतीं, बल्कि इनके माध्यम से पार्टी नेतृत्व राज्यों में अपनी राजनीतिक दिशा और प्राथमिकताओं का स्पष्ट संकेत देता है। पश्चिम बंगाल और असम दोनों ही राज्यों में भाजपा की रणनीति अलग-अलग राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है।

बंगाल में जहां राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अधिक तीव्र और बहुस्तरीय है, वहीं असम में संगठनात्मक स्थिरता और विकास एजेंडे को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे में दोनों राज्यों के लिए अलग-अलग वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी देना यह दर्शाता है कि पार्टी हर राज्य की राजनीतिक ज़मीन को अलग नजरिए से देख रही है।

आने वाले दिनों में इन पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की बैठकें होंगी, जहां नवनिर्वाचित विधायक अपने नेता का चयन करेंगे। इसके बाद चुना गया नेता राज्यपाल के समक्ष सरकार गठन का दावा पेश करेगा और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू होगी।

इस पूरे घटनाक्रम पर पूरे देश की नजर बनी हुई है, क्योंकि बंगाल और असम दोनों ही राज्यों में सरकार गठन का निर्णय न केवल स्थानीय राजनीति, बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरणों पर भी प्रभाव डाल सकता है। भाजपा की यह सक्रियता स्पष्ट रूप से संकेत देती है कि पार्टी संगठनात्मक मजबूती और सत्ता प्रबंधन दोनों मोर्चों पर पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है।

जीत के बाद सख्त संदेश: हिंसा पर ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी भाजपा, कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई की चेतावनी

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में मिली चुनावी सफलता के बाद संगठनात्मक अनुशासन और कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी तरह की चुनाव बाद हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि पार्टी कार्यकर्ता भी इसमें शामिल पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, यहां तक कि उन्हें पार्टी से निष्कासित भी किया जा सकता है।

भट्टाचार्य का यह बयान ऐसे समय आया है जब राज्य में चुनाव परिणामों के बाद तनाव और झड़पों की कुछ घटनाओं की खबरें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जीत और हार सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसके बाद हिंसा या प्रतिशोध की भावना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकती। उनके अनुसार, पार्टी का रुख पूरी तरह स्पष्ट है—कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह विपक्षी दल हो या अपनी ही पार्टी का कार्यकर्ता।

पार्टी की एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए भट्टाचार्य ने प्रशासन से भी अपील की कि जहां भी हिंसा या अशांति की घटनाएं सामने आएं, वहां तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो स्थिति और

बिगड़ सकती है।

बैठक में पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और वरिष्ठ राज्य नेतृत्व शामिल थे, जहां चुनाव परिणामों के बाद की स्थिति की समीक्षा की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से दो मुद्दों पर चर्चा हुई—पहला, चुनाव के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखना और दूसरा, पार्टी कार्यकर्ताओं के व्यवहार पर नियंत्रण सुनिश्चित करना। नेतृत्व ने यह भी तय किया कि किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि पार्टी को जनता ने एक मजबूत जनादेश दिया है, जो जिम्मेदारी के साथ आता है। ऐसे में कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है कि वे संयम और धैर्य बनाए रखें और जीत का उत्सव इस तरह मनाएं कि किसी भी व्यक्ति या समुदाय की भावनाएं आहत न हों। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि "उत्सव के नाम पर किसी को चोट पहुंचाना स्वीकार्य नहीं है।"

उन्होंने विशेष रूप से उन प्रवासी श्रमिकों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद मतदान के लिए राज्य लौटकर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। भट्टाचार्य ने कहा कि ऐसे मतदाता लोकतंत्र की असली ताकत हैं और उनकी भागीदारी का सम्मान किया जाना चाहिए।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा का यह रुख दो स्तरों पर महत्वपूर्ण है। पहला, यह संदेश विपक्ष और प्रशासन दोनों के लिए है कि पार्टी कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर गंभीर है। दूसरा, यह अपने कार्यकर्ताओं को भी अनुशासन में रखने की कोशिश है ताकि किसी भी तरह की छवि को नुकसान न पहुंचे।

पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, जहां राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पहले से ही तीव्र और संवेदनशील मानी जाती है, वहां चुनाव के बाद की स्थिति अक्सर तनावपूर्ण हो जाती है। ऐसे में किसी भी बड़े दल द्वारा संयम और शांति की अपील करना राजनीतिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि यदि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हिंसा या अवैध गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत संगठनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम पार्टी की छवि और उसकी राजनीतिक जिम्मेदारी दोनों को बनाए रखने के लिए जरूरी है।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच प्रशासन पर भी दबाव बढ़ गया है कि वह राज्य में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करे। भाजपा की इस चेतावनी और अपील के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति किस दिशा में जाती है और क्या चुनाव के बाद का तनाव जल्द नियंत्रित हो पाता है या नहीं।

फिलहाल, भाजपा का यह रुख साफ संकेत देता है कि पार्टी राजनीतिक जीत के साथ-साथ सामाजिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी को भी समान रूप से महत्व दे रही है, और किसी भी तरह की अराजकता को अपनी राजनीति का हिस्सा नहीं बनने देना चाहती।

श्रृंगेरी उपचुनाव में री-काउंटिंग से बदला नतीजा, कांग्रेस ने लगाया "वोट डकैती" का आरोप, कर्नाटक की राजनीति में भारी तनाव

बंगलूरू। कर्नाटक की राजनीति एक बार फिर तीखे विवाद और गंभीर आरोपों के केंद्र में आ गई है। कर्नाटक के श्रृंगेरी विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव की पुनर्गणना (री-काउंटिंग) के बाद घोषित परिणाम ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। जिस सीट को पहले कांग्रेस की जीत माना जा रहा था, वह अब नतीजों के उलट जाने के बाद भाजपा के पक्ष में चली गई है। इस घटनाक्रम ने राज्य की चुनावी प्रक्रिया और प्रशासनिक पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

मामले की शुरुआत उस समय हुई जब कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भाजपा उम्मीदवार डी.एन. जीवराज की याचिका पर पोस्टल बैलेट की पुनर्गणना के आदेश दिए। अदालत के निर्देश के बाद निर्वाचन आयोग की निगरानी में हुई दोबारा गिनती में बड़ा बदलाव सामने आया। पहले कांग्रेस उम्मीदवार टी.डी. राजेगौड़ा को विजेता घोषित किया गया था, लेकिन री-काउंटिंग के बाद परिणाम पलट गया और भाजपा उम्मीदवार को बढ़त मिल गई।

रिपोर्ट के अनुसार, पुनर्गणना में राजेगौड़ा के पक्ष में दर्ज 255 पोस्टल बैलेट कम पाए गए, जिससे परिणाम प्रभावित हुआ। पहले जहां कांग्रेस की 201 वोटों की बढ़त थी, वहीं बाद में यह अंतर घटकर भाजपा के पक्ष में 52 वोटों की जीत में बदल गया। इस अचानक बदलाव ने चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ा रुख अपनाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसे "सिर्फ चुनावी गड़बड़ी नहीं बल्कि सुनियोजित आपराधिक साजिश" बताया। सिद्धारमैया का आरोप है कि वैध पोस्टल बैलेट के साथ छेड़छाड़ कर परिणाम को बदला गया है। उनके अनुसार, पहले जिन मतों को वैध माना गया था, उन्हें बाद में जानबूझकर अवैध घोषित कर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि यह पूरी प्रक्रिया कांग्रेस, भाजपा और जेडीएस के कुछ एजेंटों की जानकारी के बावजूद प्रभावित हुई। उन्होंने दावा किया कि अधिकारियों ने पहले स्वीकृत वोटों पर दोबारा निशान लगाकर उन्हें अमान्य कर दिया, जिससे नतीजा प्रभावित हुआ। सिद्धारमैया ने इसे "वोट चोरी नहीं बल्कि वोट डकैती" करार दिया, जिससे राजनीतिक माहौल और अधिक गरमा गया है।

सिद्धारमैया ने निर्वाचन अधिकारी की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक की मौजूदगी के बावजूद परिणाम तुरंत घोषित कर देना नियमों के विपरीत है। उनके अनुसार, ऐसी स्थिति में पारदर्शी जांच और विस्तृत समीक्षा की आवश्यकता थी, जो नहीं की गई। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गंभीर चूक बताया है।

इस मामले में कांग्रेस उम्मीदवार टी.डी. राजेगौड़ा के चुनाव एजेंट ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पुनर्गणना की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं और जानबूझकर परिणाम को प्रभावित किया गया है। राज्य सरकार ने भी इस पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच कराने का आदेश दिया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि गड़बड़ी कहां और कैसे हुई।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला केवल एक सीट का विवाद नहीं है, बल्कि यह कर्नाटक की चुनावी व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। पोस्टल बैलेट, जो आमतौर पर संवेदनशील और निर्णायक माने जाते हैं, उनमें इस तरह की गड़बड़ी का आरोप पूरी चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है।

इस विवाद ने राज्य में कांग्रेस और भाजपा के बीच टकराव को और बढ़ा दिया है। जहां कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला बता रही है, वहीं भाजपा इसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत सही पुनर्गणना का परिणाम मान रही है। दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप से राजनीतिक माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया है।

इस बीच, सिद्धारमैया ने अन्य राज्यों की राजनीति का जिक्र करते हुए कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक बदलाव और उथल-पुथल देखी जा रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य का उल्लेख करते हुए संकेत दिया कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजनीति और अधिक जटिल हो सकती है। हालांकि, उन्होंने यह भी दावा किया कि 2028 के विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में कांग्रेस एक बार फिर मजबूत वापसी करेगी।

फिलहाल, चुनाव आयोग के पास यह मामला विचाराधीन है और सभी पक्षों की रिपोर्टों की समीक्षा की जा रही है। इस बीच, प्रशासनिक स्तर पर जांच प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार की जरूरत है, खासकर पोस्टल बैलेट और पुनर्गणना की प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है।

श्रृंगेरी का यह विवाद अब केवल एक उपचुनाव का परिणाम नहीं रहा, बल्कि यह लोकतांत्रिक संस्थाओं, चुनावी प्रक्रिया और राजनीतिक विश्वास के बीच एक बड़े टकराव का प्रतीक बन गया है, जिसका असर आने वाले समय में कर्नाटक की राजनीति पर गहरा पड़ सकता है।

संपादकीय

मौलिक प्रतिभा के विकास में है बाधक

पिछले दिनों आईआईटी खड़गपुर के डायरेक्टर प्रो. सुमन चक्रवर्ती के उस बयान ने चौंकाया कि कोचिंग के कारोबार ने छात्रों की सोचने की क्षमता को घटाया है। वे प्रतिभा विस्तार व मौलिक सोच में विकास के बजाय कोचिंग उद्योग के चतुराई के खेल में शामिल हो रहे हैं। वे दिमाग के इस्तेमाल के बजाय जेईई प्रवेश परीक्षा के लिए ट्रिक्स से गलत ऑप्शन हटाना सीख रहे हैं। फलतः वे आईआईटी जैसे उच्च संस्थानों में प्रवेश तो पा जाते हैं, लेकिन गुणवत्ता की शिक्षा से साम्य बैठाने में असफल साबित होते हैं, जिससे उनकी आईआईटी में बैक लगने यानी कुछ विषयों अनुतीर्ण होने से बैक लगने की स्थिति पैदा हो रही है। जिससे वे अक्सर तनाव में आ जाते हैं। हो सकता आने वाले समय में किसी अध्ययन व शोध से यह बात सामने आए कि उच्च तकनीक संस्थानों में बढ़ती आत्मघात की प्रवत्ति के पीछे कोचिंग संस्थानों की भेड़चाल से उपजी विसंगतियां हों। निश्चय ही यह स्थिति भारतीय उच्च व तकनीकी संस्थानों में विकसित हो रही इस नकारात्मक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली है। एक समय था कि भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाओं की प्रणाली में स्वस्थ स्पर्धा हुआ करती थी। प्रतिभावान विद्यार्थी ही उच्च तकनीकी संस्थानों में प्रवेश पा सकते थे। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बाजार के लगातार बढ़ते दखल ने सारी स्थिति ही उलट कर रख दी। वहीं दूसरी ओर सीबीएसई और अन्य शिक्षा बोर्डों द्वारा सौ फीसदी तक अंक दिए जाने ने राज्यों के बोर्डों से परीक्षा उतीर्ण करने वाले छात्रों को हीन भावना से भर दिया। निस्संदेदह, वह शिक्षा प्रणाली सवालों के दायरे में आनी चाहिए, जिसमें असंभव से लगने वाले सौ फीसदी अंक छात्रों को दिए जाते हैं। सौ फीसदी अंक एक नहीं कई-कई छात्रों को दिए जाते हैं। वहीं राज्यों के विभिन्न बोर्डों में परीक्षक कंजूसी से नंबर देकर पहले ही छात्रों को राष्ट्रीय स्पर्धा से बाहर कर देते हैं। निश्चय ही यह स्थिति देश के लाखों छात्रों के साथ अन्याय जैसी है। दरअसल, देश में पहले भी कोचिंग व्यवस्था मौजूद रही है। लेकिन एक सहायक की भूमिका में। आज कोचिंग कारोबारियों द्वारा उसे छात्रों के भविष्य का निर्धारण करने वाले एकमात्र विकल्प के रूप में बताया जा रहा है। यह व्यवस्था देश में व्याप्त आर्थिक विभेद को भी और बढ़ाती है। तय है कि संपन्न घरों से आने वाले बच्चे महंगी कोचिंग पाकर गुदड़ी के लालों के जीवन पर सदैव भारी पड़ेंगे। फलतः कुछ मध्यमवर्गीय परिवारों के अभिभावक बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए कर्ज लेकर कोचिंग का जुगाड़ करते हैं। अपना पेट काटकर वे बच्चों को महंगे कोचिंग संस्थानों में भेजते हैं। कई अभिभावक अक्सर कर्ज में डूब जाते हैं। वहीं शैक्षिक गुणवत्ता के नजरिये से देखें तो पहले जब कोचिंग एक सहायक की भूमिका में थी तो छात्र विस्तृत पढ़ाई से विषय को समझने का प्रयास करते थे। अब पूरी व्यवस्था कोचिंग केंद्रित होने से शिक्षा की व्यापकता खत्म हो रही है। इसका नकारात्मक प्रभाव यह है कि छात्र परीक्षा के तीन घंटों में सवाल समझकर हल करने की बजाय गलत विकल्पों को हटाने की कोचिंग्स द्वारा सिखायी ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। दरअसल, कोचिंग संस्थानों के तौर-तरीकों से छात्रों को 'स्पून फीडिंग' की लत लग जाती है। वहां हिंदी में पढ़ाई होती है और तैयार नोट्स को बार-बार रटाया जाता है। वहीं विडंबना यह है कि आईआईटी आदि उच्च तकनीकी संस्थानों में पढ़ाई अंग्रेजी में होती है। वहां समेस्टर सिस्टम में पढ़ाई सेल्फ-स्टडी पर आधारित होती है। यही वजह है कि महज ट्रिक्स द्वारा आईआईटी में प्रवेश करने वाले छात्र आगे की पढ़ाई के साथ साम्य नहीं बैठा पाते। उनको कई विषयों में पूरक परीक्षा देनी पड़ती है, जिससे सुनहरे सपने लेकर आए छात्र गहरे तनाव में आ जाते हैं। कई जगह होने वाले आत्मघात के पीछे यह कारण भी हो सकता है। वहीं टॉपर छात्रों को मीडिया तथा सोशल मीडिया में कोचिंग संस्थानों व अभिभावकों द्वारा सेलिब्रिटी की तरह पेश किया जाता है, जिससे वे इस ग्लैमर से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वहीं परिवार का दबाब भी तनाव बढ़ाता है। इस गंभीर स्थिति का समाधान नीति-नियंताओं का करना चाहिए।

उद्योग जगत की खुशी बंगाल के फिर से निवेश और नौकरियों का केंद्र बनने का संकेत है

> पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों का असर बाजार में भी तुरंत दिखाई दिया। सेंसेक्स में अच्छी बढ़त दर्ज की गई और कोलकाता की कई कंपनियों के शेयरों में तेजी आई। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशक स्थिर और स्पष्ट नीतियों को प्राथमिकता देते हैं।

पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम केवल राजनीतिक बदलाव ही नहीं लाये बल्कि राज्य के आर्थिक भविष्य को लेकर नई उम्मीदें भी जगाई हैं। उद्योगपति हर्ष गोयनका की प्रतिक्रिया ने इस चर्चा को और गति दी है। उन्होंने कहा है कि बंगाल का व्यापारिक वर्ग इस परिणाम से खुश है और अब विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसर सामने आ सकते हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की यह जीत ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि पहली बार उसने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के पंद्रह साल के शासन का अंत हुआ है। इस बदलाव से केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय की उम्मीद की जा रही है, जो विकास परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों का असर बाजार में भी तुरंत दिखाई दिया। सेंसेक्स में अच्छी बढ़त दर्ज की गई और कोलकाता की कई कंपनियों के शेयरों में तेजी आई। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशक स्थिर और स्पष्ट नीतियों को प्राथमिकता देते हैं। जब राज्य और केंद्र की सरकारें एक दिशा में काम करती हैं, तो निवेश का माहौल बेहतर बनता है। हालांकि, कुछ विश्लेषकों का कहना है कि बाजार की यह तेजी शुरुआती प्रतिक्रिया हो सकती है। दीर्घकाल में आर्थिक स्थिति कई अन्य कारकों पर निर्भर करेगी, जैसे वैश्विक बाजार और कच्चे तेल की कीमतें।

उद्योग जगत को उम्मीद है कि अब बड़े आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। निवेश की मंजूरी की प्रक्रिया आसान हो सकती है और नियमों में स्पष्टता आएगी। इससे निजी और सरकारी दोनों तरह के निवेश को प्रोत्साहन मिल सकता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं का विस्तार भी राज्य में तेजी से हो सकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आय और मांग बढ़ने की संभावना है। कई उद्योग संगठनों ने भी इस परिणाम का स्वागत करते हुए निवेश के माहौल में सुधार की उम्मीद जताई है।

अगर विभिन्न क्षेत्रों की बात करें, तो आधारभूत ढांचा और निर्माण क्षेत्र को सबसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। सड़क, बंदरगाह और औद्योगिक परियोजनाओं को गति मिल सकती है। अचल संपत्ति क्षेत्र में भी सुधार की उम्मीद है। चाय, कृषि और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में नई योजनाएं विकास को बढ़ावा दे सकती हैं। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में कर्ज वितरण बढ़ सकता है, खासकर छोटे उद्योगों और आवास क्षेत्र में।

इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी सामने हैं। राज्य की वित्तीय स्थिति पहले से दबाव में है। वित्तीय घाटा और कर्ज का स्तर ऊंचा बना हुआ है। ऐसे में नई सरकार के लिए अपने वादों को संतुलित तरीके से लागू करना जरूरी होगा, ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे।

विशेषज्ञों का मानना है कि केवल राजनीतिक बदलाव पर्याप्त नहीं है। नीतियों का सही क्रियान्वयन और वित्तीय अनुशासन ही लंबे समय में वास्तविक परिणाम तय करेंगे। वैसे आम लोगों के लिए इस बदलाव का अर्थ है संभावित रूप से अधिक रोजगार के अवसर और बेहतर आर्थिक गतिविधियां। अगर निवेश बढ़ता है और उद्योग विकसित होते हैं, तो राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है। इससे जीवन स्तर और बाजार की स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

हालांकि, आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल अभी भी निवेश के मामले में अन्य राज्यों से पीछे है। विदेशी निवेश कम रहा है और विनिर्माण क्षेत्र की गति भी धीमी रही है। राज्य की अर्थव्यवस्था में सेवाओं का योगदान अधिक है, जबकि औद्योगिक विकास को और मजबूत करने की जरूरत है। व्यापार करने की सुविधा से जुड़े पहलू भी महत्वपूर्ण हैं। जमीन की उपलब्धता, मंजूरी की प्रक्रिया और नियमों की पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर सुधार जरूरी है।

हम आपको याद दिला दें कि पश्चिम बंगाल का औद्योगिक इतिहास कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता था। एक समय ऐसा था जब यह राज्य अपने कारखानों और उद्योगों के कारण पूरे देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में पहचान रखता था। दूसरे राज्यों से लोग यहां रोजगार की तलाश में आते थे। लेकिन समय के साथ स्थिति बदलती चली गई। पहले वामपंथी सरकारों की नीतियों के कारण उद्योगों पर दबाव बढ़ा और धीरे धीरे कई कारखाने बंद होने लगे। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार और नीतिगत अनिश्चितता को लेकर भी सवाल उठते रहे, जिससे निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ। ममता बनर्जी के आंदोलन के चलते सिंगूर में टाटा नैनो परियोजना के बंद होने की घटना के बाद बंगाल में बड़े उद्योग लगाने को लेकर निवेशकों में एक तरह की हिचक पैदा हो गई। परिणाम यह हुआ कि रोजगार के अवसर घटे और लोगों का पलायन बढ़ने लगा। हालांकि अब जब भाजपा की सरकार बनी है, तो उद्योग जगत में एक बार फिर सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। कई उद्योग संगठनों का कहना है कि वह आने वाले समय में सरकार को नई परियोजनाओं की रूपरेखा सौंपने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को फिर से गति मिल सकती है।

बहरहाल, पश्चिम बंगाल एक नए अवसर के दौर में प्रवेश कर रहा है। अगर नई सरकार योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करती है और निवेश के अनुकूल माहौल बनाती है, तो राज्य के आर्थिक विकास को नई दिशा मिल सकती है।

प्रेरणा

सृजन की निष्ठा और कला का सत्य

कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती, वह संवेदनाओं, विचारों और जीवन के गहरे अनुभवों की अभिव्यक्ति होती है। जब कोई कलाकार अपनी रचना करता है, तो वह केवल शब्दों, रंगों या दृश्यों का संयोजन नहीं करता, बल्कि अपने भीतर के सत्य को आकार देता है। यही कारण है कि सच्ची कला हमेशा समय की सीमाओं को पार कर जाती है और युगों तक लोगों के हृदय में जीवित रहती है। इसी सत्य का एक अद्भुत उदाहरण हैं शैलेंद्र और उनके द्वारा निर्मित फिल्म तीसरी कसम, जो कला के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

यह वह समय था जब हिंदी सिनेमा तेजी से व्यावसायिकता की ओर बढ़ रहा था। फिल्मों की सफलता का पैमाना बॉक्स ऑफिस पर मिलने वाला लाभ बन चुका था। ऐसे माहौल में एक कलाकार के लिए अपनी रचना के मूल स्वरूप को बनाए रखना आसान नहीं था। लेकिन शैलेंद्र उन कलाकारों में से थे, जो कला को बाजार के तराजू पर तौलने में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने अपने साहित्यिक मित्र फणीश्वरनाथ 'रेणु' की कहानी को फिल्म के रूप में प्रस्तुत करने का निश्चय किया। यह कहानी केवल एक कथा नहीं थी, बल्कि भारतीय ग्रामीण जीवन की आत्मा को दर्शाने वाली एक मार्मिक अभिव्यक्ति थी।

जब फिल्म बनकर तैयार हुई और कुछ वितरकों को दिखाई गई, तो उनकी प्रतिक्रिया व्यावसायिक दृष्टिकोण से स्वाभाविक थी। उन्होंने कहा कि फिल्म का अंत निराशाजनक है और यदि इसे बदल दिया जाए, तो यह दर्शकों को अधिक आकर्षित कर सकती है। यह सुझाव उस समय की फिल्म इंडस्ट्री की मानसिकता को दर्शाता है, जहां कला की बजाय दर्शकों की तात्कालिक पसंद को अधिक महत्व दिया जाता था। लेकिन यही वह क्षण था, जब शैलेंद्र की प्रतिबद्धता की असली परीक्षा हुई।

उन्होंने तुरंत अपने मित्र रेणु की ओर देखा, जो इस सुझाव से स्पष्ट रूप से आहत थे। एक लेखक के लिए उसकी रचना केवल शब्दों का समूह नहीं होती, बल्कि उसकी आत्मा का विस्तार होती है। उस रचना में बदलाव करना उसके मूल भाव को बदलने जैसा होता है। शैलेंद्र ने इस भावना को समझा और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना निर्णय सुना दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कुछ बातें लाभ-हानि के चक्र से परे होती हैं और कला उन्हीं में से एक है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने यह फिल्म मुनाफा कमाने के लिए नहीं बनाई है, बल्कि एक सच्ची कहानी को उसी रूप में प्रस्तुत करने के लिए बनाई है, जैसा वह है।

यह निर्णय केवल एक फिल्म के अंत को बनाए रखने का नहीं था, बल्कि यह कला के मूल्यों की रक्षा करने का निर्णय था। यह उस सोच के खिलाफ खड़ा होना था, जो हर चीज को बाजार के हिसाब से ढालने की कोशिश करती है। शैलेंद्र ने यह दिखाया कि एक सच्चा कलाकार वही होता है, जो अपने सृजन के प्रति ईमानदार रहता है, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।

समय ने साबित किया कि उनका निर्णय सही था। भले ही उस समय फिल्म को तुरंत व्यावसायिक सफलता नहीं मिली, लेकिन उसकी गुणवत्ता और गहराई को समय के साथ लोगों ने समझा। फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और आज यह भारतीय सिनेमा की 'कल्ट' फिल्मों में गिनी जाती है। यह केवल एक फिल्म की सफलता नहीं थी, बल्कि यह उस विचार की जीत थी कि सच्ची कला कभी नष्ट नहीं होती, वह अपने समय से आगे जाकर भी लोगों के दिलों में जगह बना लेती है।

यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिबद्धता का कितना महत्व है। जब हम किसी कार्य को केवल लाभ के लिए करते हैं, तो उसमें स्थायित्व नहीं होता। लेकिन जब हम उसे अपने विश्वास और निष्ठा के साथ करते हैं, तो वह कार्य अपने आप में एक मूल्य बन जाता है। शैलेंद्र का यह निर्णय केवल उनके व्यक्तित्व को नहीं दर्शाता, बल्कि यह उन सभी कलाकारों के लिए प्रेरणा है, जो अपनी कला के साथ समझौता करने के लिए मजबूर होते हैं।

आज के दौर में, जब हर चीज तेजी से बदल रही है और सफलता को केवल लोकप्रियता और लाभ से मापा जाता है, तब यह कहानी और भी प्रासंगिक हो जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची सफलता वह नहीं होती, जो तुरंत दिखाई दे, बल्कि वह होती है, जो समय की कसौटी पर खरी उतरे। कला का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को सोचने के लिए प्रेरित करना भी होता है। और जब कोई कलाकार इस उद्देश्य को समझता है, तब उसकी रचना एक साधारण कृति से कहीं अधिक बन जाती है। शैलेंद्र और रेणु की यह कहानी हमें यह भी बताती है कि सृजन केवल व्यक्तिगत प्रयास नहीं होता, बल्कि यह सहयोग और समझ का परिणाम होता है। जब दो सृजनशील व्यक्ति एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं, तो उनकी कृति में एक अलग ही गहराई आ जाती है। यही कारण है कि 'तीसरी कसम' आज भी लोगों के दिलों को छूती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है। अंततः, यह कहा जा सकता है कि कला और प्रतिबद्धता का संबंध बहुत गहरा है। जहां प्रतिबद्धता होती है, वहीं सच्ची कला जन्म लेती है। शैलेंद्र ने अपने निर्णय से यह सिद्ध कर दिया कि कला को किसी भी कीमत पर समझौते का विषय नहीं बनाया जा सकता। उनका यह साहस और विश्वास आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहें और अपने मूल्यों से कभी समझौता न करें। यही सच्ची सफलता है, यही सच्ची कला है, और यही वह विरासत है, जो समय के साथ और भी मजबूत होती जाती है।

क्या कहते हैं विधानसभा चुनावों के नतीजे

बीते अप्रैल में हुए पांच राज्यों के चुनाव नतीजों को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं। लेकिन देश के पूर्वी छोर पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक स्थित चार राज्यों के नतीजों को देखें तो उनमें एक बात समान नजर आती है। सभी राज्यों ने अपने यहां के उन आक्रामक नेतृत्व पर भरोसा जताया है, जिनसे विकास और नवाचार की उम्मीद है। असम में हिमंत, पश्चिम बंगाल में बीजेपी और तमिलनाडु में विजयन की जीत लोकांक्षाओं के जमीनी हकीकत बनने का भरोसा है। इन राज्यों की जीत में दिखता है कि केंद्र से बिना वजह की लड़ाई का भी कोई मोल नहीं है। आज की जनता विकास चाहती है, महिलाएं सुरक्षा चाहती हैं और युवा अपने भविष्य और सपनों की गारंटी चाहते हैं। इस बार चुनाव तो पांच राज्यों में हुए, लेकिन सबसे ज्यादा में चर्चा पश्चिम बंगाल का चुनाव रहा। उन्तीस अप्रैल को आखिरी दौर के मतदान के बाद आए एक्जिट पोल के नतीजों को लेकर काफी सवाल भी उठे, खासकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार की आशंका को लेकर एक्जिट पोल निशाने पर भी रहे। सिर्फ एक एक्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया ने तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजयन की पार्टी टीवीके के जीत की संभावना जताई थी। जबकि किसी भी एक्जिट पोल को तमिलनाडु में टीवीके की जीत की उम्मीद नहीं थी।

सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी को क्यों हार मिली? इसमें दो राय नहीं कि 2011 से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल था। फिर भी बौद्धिकों के एक वर्ग को लगता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनावों के वोट के अंतर को पाटकर जीत दर्ज कर लेगी। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 38 प्रतिशत वोट और 77 सीटें मिली थीं। 2016 के विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी को 10 प्रतिशत से कुछ ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन उसे सिर्फ तीन सीटें ही मिली थीं। उसकी तुलना में देखें तो बीजेपी के लिए 2021 के चुनावी नतीजे बड़ी छलांग थे। इस ट्रेंड के हिसाब से इस बार बीजेपी की जीत सुनिश्चित लग रही थी, हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को अपने पिछले प्रदर्शन से छह सीटें कम पर संतोष करना पड़ा था। इसलिए बीजेपी की जीत को लेकर संशय भी था। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में जीत हासिल करने के लिए चुनावी रणनीति बनाई, खुद कई रोड शो किए, झारग्राम जिले में सड़क पर उतर कर बंगाल की प्रसिद्ध झालमुढ़ी का स्वाद चखा, उसने भाजपा की संभावनाओं के द्वार खोल दिए। रही-सही कसर ममता बनर्जी की कुछ गलतियों ने कर दिए। बीते साल अगस्त में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म और उसकी हत्या पर ममता ने जिस तरह की चलताऊ राजनीति की, उससे पश्चिम बंगाल गुस्से में था। इसका असर भी दिखा और महिलाओं ने उनकी लक्ष्मी भंडार योजना में मिल रही डेढ़ हजार रूपए की रकम पर भरोसा नहीं किया और ममता को हार का सामना करना पड़ा। ममता ने भाजपा से लोगों को डराते हुए कहा कि अगर राज्य में उसकी सरकार आ गई तो वह माछ-भात खाने पर रोक लगा देगी। ममता की खासियत उनकी आक्रामक राजनीतिक शैली रही है। लेकिन इस बार उनकी वह आक्रामकता ठोस मुद्दों की बजाय हल्की बातों में ज्यादा नजर आई। इसलिए उनके खिलाफ भाजपा का भय बनाम भरोसा का नारा चल गया। भारतीय जनता पार्टी की जीत में उसके रणनीतिकार अमित शाह की बड़ी भूमिका रही। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव अभियान में घुसपैठ को मुद्दा बनाए रखा। ममता बनर्जी घुसपैठ को चलताऊ और हिंदू-मुस्लिम के बीच खाई बढ़ाने की राजनीति के मुद्दे के तौर पर लेती रहीं। भारतीय जनता पार्टी अब संतोष कर सकती है कि उसके पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रस्दा मुखर्जी के घर में भी उसका शासन है।

असम के लिए घुसपैठ का मुद्दा पुराना है। हिमंत विस्वसरमा ने इस मुद्दे को खूब हवा दी। उन्होंने बार-बार कहा कि वे सत्ता में लौटे तो किसी भी घुसपैठिए को असम में नहीं रहने देंगे। असम की जनसांख्यिकी को घुसपैठ ने बहुत प्रभावित किया है। इससे असम के लोग बहुत प्रभावित हैं। अतीत में कांग्रेस की सरकारों ने इसकी तरफ या तो आंख मूंदे रखा या फिर घुसपैठियों को अपने वोट बैंक के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। इससे असम का बहुसंख्यक वर्ग नाराज हुआ। वैसे हिमंत भी पुराने कांग्रेसी हैं। उन्हें कांग्रेस की अंदरूनी कमजोरियां भी पता हैं। फिर अपने पांच साल के कार्यकाल में उन्होंने विकास को गति भी दी है। इसकी वजह से असम के लोगों ने उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। तीसरे बड़े राज्य तमिलनाडु में पिछले यानी 2021 के विधानसभा चुनाव में डीएमके ने भले ही गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन पच्चीस साल बाद वह अकेले दम पर 133 सीटों के साथ बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही। लेकिन पूरे पांच साल के शासन काल में स्टालिन की सरकार की उपलब्धि खोजेंगे तो पाएंगे कि वह पूरे कार्यकाल में सनातन पर हमले करती रही। उसके निशाने पर नरेंद्र मोदी की सरकार रही। हिंदी को मुद्दे पर भी वह तमिलनाडु के लोगों की गोलबंदी करती रही। उसने नई शिक्षा नीति को तमिल अस्मिता के लिए खतरा बताया। प्रस्तावित लोकसभा सीटों के परिसीमन को भी मुद्दा बनाया। उसके बरक्स अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजयन की पार्टी टीवीके ने लोगों के बीच पैठ बनाई। लोगों की भलाई के लिए काम किए। ठीक है कि विजयन का क्रेज युवाओं में ज्यादा है। लेकिन लोकभलाई के लिए किए गए कार्यों की वजह से वे तमिलनाडु के वरिष्ठ नागरिकों के भी चहेते बने। यही वजह है कि उनका दल राज्य में सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है। सत्ताधारी डीएमके दूसरे स्थान पर पिछड़ गया है।

अभियान

श्री लक्ष्मी साधना का रहस्य: मंत्र, मन और समृद्धि का अदृश्य संगम

भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में जब भी धन, सौभाग्य और समृद्धि की चर्चा होती है, तो सबसे पहले स्मरण होता है मां लक्ष्मी का, जिन्हें ऐश्वर्य, वैभव और शुभता की अधिष्ठात्री माना गया है। यह केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक विज्ञान भी कार्य करता है। शुक्रवार का दिन विशेष रूप से लक्ष्मी साधना के लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिन सौंदर्य, संतुलन और आकर्षण की ऊर्जा से जुड़ा होता है। जब कोई साधक इस दिन श्रद्धा और विधि से मंत्रों का जाप करता है, तो वह केवल पूजा नहीं करता, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है।

मंत्रों की शक्ति को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि हर ध्वनि एक विशेष कंपन उत्पन्न करती है। जब इन ध्वनियों को निश्चित क्रम और लय में उच्चारित किया जाता है, तो वे एक ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जो साधक के मन और वातावरण को प्रभावित करता है। यही कारण है कि बीज मंत्रों को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। ये छोटे-छोटे शब्द होते हैं, लेकिन इनमें अपार ऊर्जा संचित होती है। "ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं" ऐसा ही एक बीज मंत्र है, जो लक्ष्मी साधना का मूल माना जाता है।

इस मंत्र में "श्रीं" धन और समृद्धि का प्रतीक है, "ह्रीं" आंतरिक शुद्धता और दिव्यता का संकेत देता है, और "क्लीं" आकर्षण की शक्ति को दर्शाता है। जब इन तीनों का संयुक्त जाप किया जाता है, तो यह साधक के जीवन में एक संतुलित ऊर्जा प्रवाह उत्पन्न करता है। यह केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यक्ति के आत्मविश्वास, मानसिक शांति और निर्णय क्षमता को भी मजबूत बनाता है। नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के विचारों में सकारात्मकता आती है और वह अपने जीवन के लक्ष्यों को अधिक स्पष्टता से देख पाता है।

लक्ष्मी साधना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया भी है। जब कोई व्यक्ति मंत्र जाप करता है, तो उसका मन धीरे-धीरे शांत होने लगता है। यह शांति उसे अपने भीतर झांकने का अवसर देती है, जहां वह अपने भय, संदेह और नकारात्मक विचारों को पहचान पाता है। जब ये नकारात्मक तत्व दूर होते हैं, तभी वास्तविक समृद्धि का मार्ग खुलता है।

महालक्ष्मी मंत्र "ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः" साधना के उच्च स्तर का प्रतीक है। इस मंत्र में देवी के कृपालु स्वरूप का आह्वान किया जाता है। "कमल" यहां केवल एक फूल नहीं, बल्कि शुद्धता और निर्लिप्तता का प्रतीक है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही साधक को भी जीवन की कठिनाइयों के बीच संतुलित और सकारात्मक बने रहना चाहिए। इस मंत्र का नियमित जाप व्यक्ति को यह आंतरिक शक्ति प्रदान करता है।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि मंत्र केवल शब्द नहीं होते, बल्कि वे एक संकल्प के साथ जुड़े होते हैं। यदि व्यक्ति केवल औपचारिकता के रूप में मंत्र जाप करता है, तो उसका प्रभाव सीमित रह जाता है। लेकिन जब वही मंत्र पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता के साथ जपा जाता है, तो वह जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकता है। यह परिवर्तन धीरे-धीरे होता है, लेकिन स्थायी होता है।

"या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता" यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि हर छोटे-बड़े अनुभव में मौजूद है। जब हम इस भावना को अपनाते हैं, तो हमारे भीतर कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है। कृतज्ञता वह शक्ति है, जो जीवन में और अधिक सकारात्मकता और अवसरों को आकर्षित करती है। यही कारण है कि इस श्लोक का जाप केवल पूजा का हिस्सा नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन भी है।

जीवन में आने वाली बाधाएं अक्सर हमारे अपने ही डर और संदेह का परिणाम होती हैं। "ॐ ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः" मंत्र इन बाधाओं को दूर करने में सहायक माना जाता है। यह मंत्र साधक के मन को स्थिर करता है और उसे अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करता है। जब मन शांत और स्पष्ट होता है, तो निर्णय लेना आसान हो जाता है और कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

आर्थिक तंगी और कर्ज से मुक्ति के लिए "ॐ ह्रीं श्री क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये" मंत्र का विशेष महत्व है। यह मंत्र व्यक्ति के जीवन में आर्थिक स्थिरता लाने के लिए जपा जाता है। लेकिन इसके साथ यह समझना भी आवश्यक है कि केवल मंत्र जाप ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ परिश्रम, ईमानदारी और सही दिशा में प्रयास भी जरूरी हैं। मंत्र साधना हमें मानसिक शक्ति देती है, जिससे हम अपने प्रयासों को सही दिशा में लगा सकें।

आज के आधुनिक जीवन में, जहां प्रतिस्पर्धा और तनाव लगातार बढ़ रहे हैं, वहां लक्ष्मी साधना एक संतुलन प्रदान करती है। यह हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष से भी आती है। जब व्यक्ति इन दोनों के बीच संतुलन बना लेता है, तभी वह वास्तव में समृद्ध कहलाता है। लक्ष्मी कृपा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है, तो उसका प्रभाव उसके परिवार, समाज और आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। वह दूसरों की मदद करने में सक्षम होता है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में योगदान देता है। इस प्रकार, लक्ष्मी साधना केवल व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक समृद्धि का भी आधार बन सकती है।

अंततः, यह समझना आवश्यक है कि मंत्र शक्ति एक सूक्ष्म विज्ञान है, जो धैर्य और विश्वास की मांग करता है। यदि इसे सही तरीके से अपनाया जाए, तो यह जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल पूजा और मंत्र जाप ही नहीं, बल्कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण और सच्चे कर्म भी आवश्यक हैं। जब ये सभी तत्व एक साथ मिलते हैं, तब व्यक्ति के जीवन में वास्तविक समृद्धि का उदय होता है।

यही वह मार्ग है, जो हमें सिखाता है कि सच्ची संपत्ति केवल धन नहीं, बल्कि एक संतुलित, शांत और संतुष्ट जीवन है। और जब यह संतुलन प्राप्त हो जाता है, तब हर दिन, हर क्षण एक उत्सव बन जाता है—एक ऐसा उत्सव, जिसमें लक्ष्मी की कृपा निरंतर बनी रहती है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

राजस्थान मॉडल की रणनीति से बंगाल में भाजपा का बड़ा उलटफेर, संगठनात्मक ताकत बनी जीत की रीढ़

पश्चिम बंगाल का हालिया चुनाव परिणाम केवल सत्ता परिवर्तन की एक सामान्य राजनीतिक घटना नहीं रहा, बल्कि इसने भारतीय लोकतंत्र में चुनावी रणनीति के बदलते स्वरूप को भी स्पष्ट रूप से सामने ला दिया है। यह परिणाम इस बात का संकेत है कि अब चुनाव केवल जनसभाओं, नारों और करिश्माई नेतृत्व के भरोसे नहीं जीते जाते, बल्कि इसके पीछे एक गहरी, बहुस्तरीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तैयार की गई रणनीति की आवश्यकता होती है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सफलता को जिस ढांचे ने सबसे अधिक प्रभावित किया, उसे राजनीतिक विश्लेषकों ने "राजस्थान मॉडल" के रूप में परिभाषित किया है। यह मॉडल न केवल संगठनात्मक मजबूती का उदाहरण है, बल्कि यह आधुनिक चुनावी प्रबंधन का एक सशक्त प्रतिरूप भी बनकर उभरा है।

इस मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसमें चुनाव को एक समग्र प्रक्रिया के रूप में देखा गया, जिसमें हर स्तर—बूथ से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक—एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। पारंपरिक राजनीति में जहां चुनावी अभियान अक्सर शीर्ष स्तर पर केंद्रित रहता था, वहीं इस मॉडल ने जमीनी स्तर को केंद्र में रखा। हर बूथ को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में देखा गया और वहां कार्यरत कार्यकर्ताओं को स्पष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इस दृष्टिकोण ने पार्टी को मतदाताओं के साथ सीधा और प्रभावी संवाद स्थापित करने में मदद की।

इस रणनीति के क्रियान्वयन में जिन नेताओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण रही, उनमें गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी प्रमुख हैं। इन दोनों नेताओं ने उत्तर बंगाल के क्षेत्रों—सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूच बिहार—में जमीनी स्तर पर व्यापक अभियान चलाया। उन्होंने केवल राजनीतिक रैलियों तक अपने आप को सीमित नहीं रखा, बल्कि कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित किया, स्थानीय मुद्दों को समझा और उन्हें चुनावी रणनीति में शामिल किया। यह एक ऐसा दृष्टिकोण था, जिसने पार्टी को उन क्षेत्रों में भी मजबूत बनाया, जहां पहले उसकी पकड़ कमजोर मानी जाती थी।

उत्तर बंगाल में भाजपा का प्रदर्शन इस चुनाव की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी बनकर सामने आया। 28 में से 27 सीटों पर जीत केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि संगठनात्मक रणनीति कितनी प्रभावी रही। यह सफलता बूथ स्तर पर किए गए सूक्ष्म प्रबंधन, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और क्षेत्रीय नेतृत्व के समन्वय का परिणाम थी। इसने यह भी दिखाया कि यदि किसी

क्षेत्र में लगातार और योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए, तो वहां की राजनीतिक धारा को बदला जा सकता है।

चुनावी प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री की रैलियों और रोड शो का प्रबंधन भी इस मॉडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। अरुण चतुर्वेदी और अशोक परनामी ने इस जिम्मेदारी को संभालते हुए यह सुनिश्चित किया कि हर रैली केवल एक राजनीतिक आयोजन न होकर एक संगठित संदेश का माध्यम बने। जिन क्षेत्रों में ये रैलियां आयोजित की गईं, वहां भाजपा को लगभग 75 प्रतिशत सीटों पर सफलता मिली। यह आंकड़ा इस बात का स्पष्ट संकेत है कि संदेश की प्रस्तुति और उसका सही समय पर सही स्थान तक पहुंचना कितना महत्वपूर्ण होता है।

इस मॉडल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी—फीडबैक सिस्टम। चुनाव के दौरान लगातार जमीनी स्तर से जानकारी जुटाई जाती रही, जिससे पार्टी को यह समझने में मदद मिली कि कहां क्या बदलाव करने की आवश्यकता है। यह एक गतिशील प्रक्रिया थी, जिसमें रणनीति को परिस्थितियों के अनुसार लगातार संशोधित किया जाता रहा। इससे पार्टी को हर क्षेत्र में अपनी रणनीति को स्थानीय जरूरतों के अनुसार ढालने का अवसर मिला।

इस पूरी प्रक्रिया में सी.पी. जोशी ने केंद्रीय नेतृत्व और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु की भूमिका निभाई। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि पार्टी की रणनीति का क्रियान्वयन बिना किसी बाधा के हो और हर स्तर पर समन्वय बना रहे। उनकी भूमिका इस बात को सुनिश्चित करने में थी कि केंद्रीय संदेश जमीनी स्तर तक सही तरीके से पहुंचे और स्थानीय मुद्दों को भी रणनीति में उचित स्थान मिले।

आसनसोल जैसे क्षेत्रों में इस रणनीति का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिला। आसनसोल में पार्टी ने सभी सीटों पर जीत दर्ज कर पिछली बार के मुकाबले प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार किया। वहीं, कोलकाता उत्तर और कोलकाता दक्षिण जैसे पारंपरिक गढ़ों में भी भाजपा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह इस बात का संकेत है कि पार्टी ने केवल ग्रामीण क्षेत्रों पर ही नहीं, बल्कि शहरी और विविध मतदाता वर्गों पर भी समान रूप से ध्यान दिया।

इस चुनाव ने यह भी स्पष्ट किया कि अब भारतीय राजनीति में डेटा और विश्लेषण का महत्व बढ़ता जा रहा है। "राजस्थान मॉडल" में हर निर्णय डेटा के आधार पर लिया गया। मतदाता सूची का विश्लेषण, मतदान प्रतिशत का अध्ययन और विभिन्न सामाजिक समूहों के व्यवहार को समझकर रणनीति तैयार की गई। इससे पार्टी को यह समझने में मदद मिली कि किस क्षेत्र में किस प्रकार का संदेश अधिक प्रभावी होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस चुनाव में भाजपा की सफलता का सबसे बड़ा कारण उसका "संगठन आधारित चुनाव प्रबंधन" रहा। इसमें हर कार्यकर्ता को एक जिम्मेदारी दी गई और हर बूथ को एक रणनीतिक इकाई के रूप में देखा गया। इससे न केवल चुनावी प्रचार अधिक प्रभावी हुआ, बल्कि मतदाताओं के साथ सीधा संपर्क भी स्थापित हुआ।

राजनीतिक दृष्टि से यह चुनाव केवल पश्चिम बंगाल की सत्ता का प्रश्न नहीं था, बल्कि यह इस बात का भी परीक्षण था कि क्या संगठित और डेटा आधारित चुनावी रणनीति पारंपरिक राजनीतिक ढांचों को चुनौती दे सकती है। परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसा संभव है, यदि योजना, नेतृत्व और जमीनी कार्य समान रूप से मजबूत हों।

अब भाजपा इस मॉडल को एक राष्ट्रीय चुनावी रणनीति के रूप में विकसित करने की दिशा में देख रही है। पार्टी के भीतर यह चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले राज्यों के चुनावों में भी इसी तरह के संगठनात्मक ढांचे को अपनाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि "राजस्थान मॉडल" अब केवल एक राज्य विशेष की रणनीति न रहकर एक व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण का हिस्सा बन सकता है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस मॉडल ने केवल चुनाव जीतने की रणनीति नहीं दी, बल्कि यह संगठन को मजबूत करने का भी एक प्रभावी माध्यम बना। इससे पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं की भूमिका और महत्व दोनों बढ़े हैं। हर कार्यकर्ता को यह महसूस हुआ कि वह चुनावी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे उसकी सक्रियता और प्रतिबद्धता में वृद्धि हुई।

अंततः, पश्चिम बंगाल का यह चुनाव परिणाम भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा सकता है। इसने यह साबित कर दिया है कि आधुनिक समय में चुनाव केवल भावनाओं और नारों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें रणनीति, संगठन और प्रबंधन की समान रूप से आवश्यकता होती है। "राजस्थान मॉडल" इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसने यह दिखाया है कि यदि सही दृष्टिकोण अपनाया जाए, तो किसी भी राजनीतिक चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है।

कुल मिलाकर, यह चुनाव परिणाम केवल एक जीत नहीं है, बल्कि यह एक नई राजनीतिक सोच की शुरुआत है। यह उस भविष्य की ओर संकेत करता है, जहां चुनावी राजनीति अधिक संगठित, डेटा-आधारित और रणनीतिक होगी। भारतीय लोकतंत्र के इस नए अध्याय में "राजस्थान मॉडल" एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु बनकर उभरा है, जो आने वाले वर्षों में राजनीति की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित कर सकता है।

सूरत-मुंबई कपड़ा व्यापार को नई मजबूती देने की पहल, फोस्टा बैठक में बने कई अहम प्रस्ताव

सूरत। देश के टेक्सटाइल हब माने जाने वाले सूरत और व्यापारिक राजधानी मुंबई के बीच कपड़ा उद्योग को अधिक संगठित, सुरक्षित और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। इसी क्रम में मंगलवार, 5 मई 2026 को सूरत स्थित फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन के कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें दोनों शहरों के व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

यह बैठक केवल औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसे कपड़ा व्यापार के भविष्य की दिशा तय करने वाली एक रणनीतिक चर्चा के रूप में देखा जा रहा है। बैठक का मुख्य उद्देश्य सूरत और मुंबई के बीच कपड़ा व्यापार को मजबूत करना, व्यापारिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना और व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं का संयुक्त समाधान ढूंढना था। इस बैठक में फोस्टा के महामंत्री दिनेश कटारिया के साथ मुंबई के मार्केट सिल्क मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी भी शामिल हुए। इनमें उपाध्यक्ष हर्षदभाई शाह, सचिव आश्विन मलकन और कमिटी सदस्य अतुष मेहता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। दोनों संगठनों के बीच हुई यह चर्चा कपड़ा उद्योग में सहयोग और समन्वय को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है।

बैठक में सबसे अधिक जोर व्यापारिक स्थिरता और भुगतान सुरक्षा पर दिया गया। हाल के वर्षों में कपड़ा व्यापार में

भुगतान से जुड़ी चुनौतियां बढ़ी हैं, जिससे छोटे और मध्यम व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इस समस्या के समाधान के लिए दोनों संगठनों ने एक साझा नेटवर्क या संयुक्त ग्रुप बनाने पर सहमति जताई, जिसका उद्देश्य संदिग्ध व्यापारियों और धोखाधड़ी करने वाले तत्वों पर नियंत्रण रखना होगा।

इसके अलावा, बैठक में सरकारी विभागों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। व्यापारियों का मानना है कि कई बार नियमों की अस्पष्टता और प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण व्यापार प्रभावित होता है। ऐसे में उद्योग और प्रशासन के बीच संवाद को मजबूत करना आवश्यक है।

जीएसटी से जुड़े मुद्दे बैठक का एक प्रमुख केंद्र रहे। वर्तमान में 2499 से अधिक कीमत वाले गारमेंट पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू है, जिसे व्यापारियों ने एक बड़ी बाधा के रूप में बताया। बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया कि इस सीमा को बढ़ाकर 7500 किया जाए, ताकि मध्यम वर्गीय व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिल सके। इस प्रस्ताव को आगे सरकार के समक्ष औपचारिक रूप से प्रस्तुत करने पर सहमति बनी।

फोस्टा प्रतिनिधियों ने बताया कि कपड़ा उद्योग देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, और इसमें सूरत तथा मुंबई की भूमिका बेहद अहम है। सूरत जहां उत्पादन और थोक व्यापार का केंद्र है, वहीं मुंबई फैशन और वितरण नेटवर्क का बड़ा हब माना जाता है। ऐसे में दोनों शहरों के बीच समन्वय बढ़ने से पूरे उद्योग को लाभ मिलेगा।

बैठक में यह भी चर्चा हुई कि कपड़ा व्यापार को डिजिटल और संगठित ढांचे में लाना समय की जरूरत है। इसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने पर विचार किया गया, जहां व्यापारी सुरक्षित तरीके से लेनदेन कर सकें और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना कम हो।

फोस्टा ने यह भी बताया कि यह पहली बार नहीं है जब संगठन ने अन्य शहरों के व्यापारिक संगठनों के साथ संवाद स्थापित किया है। इससे पहले अहमदाबाद, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों के कपड़ा संगठनों के साथ भी इसी तरह की चर्चाएं हो चुकी हैं। इसका उद्देश्य पूरे देश में कपड़ा व्यापार को एकीकृत और मजबूत नेटवर्क के रूप में विकसित करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस तरह की पहलें सफल होती हैं, तो भारतीय कपड़ा उद्योग वैश्विक स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकता है। विशेष रूप से सूरत और मुंबई जैसे शहरों के बीच सहयोग बढ़ने से निर्यात, रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे।

बैठक के अंत में सभी प्रतिनिधियों ने इस बात पर सहमति जताई कि कपड़ा व्यापार को केवल प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं, बल्कि सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इससे न केवल व्यापारियों को लाभ होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी बेहतर गुणवत्ता और उचित कीमत पर उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे।

कुल मिलाकर यह बैठक कपड़ा उद्योग के लिए एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखी जा रही है, जो आने वाले समय में सूरत और मुंबई के बीच व्यापारिक संबंधों को और अधिक मजबूत और संगठित बना सकती है।

वडोदरा में पीएम मोदी के संभावित दौरे को लेकर हाई अलर्ट, सरदार धाम-3 उद्घाटन की तैयारियां तेज

वडोदरा। गुजरात के वडोदरा शहर में आगामी दिनों में एक बड़े कार्यक्रम की आहट के साथ प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। नेशनल हाईवे-48 पर वाघोडिया क्रॉसिंग स्थित नव-निर्मित सरदार धाम-3 के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में है और विभिन्न स्तरों पर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया है।

यह दौरा केवल एक उद्घाटन समारोह भर नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक बड़े जनसंपर्क और राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में देखा जा रहा है। संभावित कार्यक्रम के अनुसार, प्रधानमंत्री 11 मई को दोपहर के समय इस भव्य परिसर का उद्घाटन कर सकते हैं। इस दौरान वे सरदार धाम-3 में निर्मित आधुनिक सुविधाओं जैसे हॉस्टल, लाइब्रेरी और अन्य संरचनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। प्रशासन ने कार्यक्रम के सुचारु संचालन के लिए बहुस्तरीय योजना तैयार की है। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर डॉ. अनिल धामेलिया, एडिशनल पुलिस कमिश्नर नीलेश जाजड़िया, जिला विकास अधिकारी ममता हिरपरा और

पुलिस अधीक्षक सुशील अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से सौंप दी गई हैं, ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

इस कार्यक्रम में गुजरात के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इसे देखते हुए भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात नियंत्रण को लेकर विशेष रणनीति बनाई गई है। पुलिस विभाग और प्रशासनिक टीमें मिलकर सुरक्षा के बहुस्तरीय इंतजाम सुनिश्चित कर रही हैं, जिसमें वीआईपी सुरक्षा के साथ-साथ आम नागरिकों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद उनके वापसी मार्ग को भी विशेष रूप से सजाया और व्यवस्थित किया जा रहा है। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा हरनी झील के पास गडा सर्कल से एयरपोर्ट तक के मार्ग पर विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस पूरे रूट का निरीक्षण म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया, ताकि यातायात सुचारु रहे और स्वागत कार्यक्रम व्यवस्थित ढंग से आयोजित हो सके।

इस आयोजन में स्थानीय ट्रस्ट की भी अहम भूमिका है। सरदार धाम ट्रस्ट के ट्रस्टी घनश्यामभाई बोरड और रमेशभाई लिंबानी ने प्रशासन को कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी और आम जनता के लिए की जा रही व्यवस्थाओं से अवगत कराया। ट्रस्ट द्वारा पार्किंग, बैठने की व्यवस्था, भोजन और परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

कलेक्टर ने ट्रस्ट के प्रयासों की सराहना करते हुए सुझाव दिए कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से पार्किंग व्यवस्था और यातायात नियंत्रण पर ध्यान देने को कहा, ताकि कार्यक्रम स्थल के आसपास जाम जैसी स्थिति न बने।

इस पूरे आयोजन के लिए प्रशासन ने अलग-अलग समितियों का गठन किया है, जिनमें सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता और जनसंपर्क जैसे विभिन्न विभागों को शामिल किया गया है। हर समिति को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं और समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं, ताकि तैयारियों में कोई कमी न रह जाए।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बड़े आयोजनों में प्रशासनिक समन्वय और पूर्व तैयारी बेहद महत्वपूर्ण होती है। वडोदरा प्रशासन जिस तरह से सक्रियता दिखा रहा है, उससे यह संकेत मिलता है कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

फिलहाल, शहर में इस संभावित दौरे को लेकर उत्साह और तैयारियों का माहौल है। जहां एक ओर प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को लेकर सतर्क है, वहीं आम लोगों में भी इस कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रधानमंत्री का यह दौरा किस प्रकार वडोदरा और पूरे गुजरात के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होता है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अडालज स्थित त्रिमंदिर परिसर में राजस्व विभाग के तीन दिवसीय चिंतन शिविर का प्रारंभ कराया

▸▸ कोलोबरेट, इनोवेट एंड ट्रांसफॉर्म फॉर बेटर लैंड गवर्नेंस थीम के साथ राजस्व अधिकारियों-जिला कलेक्टरों का सामूहिक चिंतन-मंथन

▸▸ चिंतन शिविर स्वयं के साथ संवाद तथा छोटे से छोटे व्यक्ति के सुख-समृद्धि एवं कल्याण के चिंतन का सक्षम माध्यम है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ पूज्य श्री दीपकभाई देसाई ने राजस्व अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रेरणादायी प्रवचन से प्रोत्साहित किया

▸▸ प्रशासनिक प्रक्रिया को नागरिकों की सेवा मानकर जन समस्याओं को हल करना राज्य सरकार की प्राथमिकता : राजस्व राज्य मंत्री श्री संजयसिंह महीडा

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को राज्य सरकार के राजस्व विभाग के तीन दिवसीय चिंतन शिविर का प्रारंभ कराते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि चिंतन शिविर स्वयं के साथ संवाद एवं छोटे से छोटे व्यक्ति के सुख-समृद्धि एवं कल्याण के चिंतन का सक्षम माध्यम है।

इस संदर्भ में श्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार के महत्वपूर्ण राजस्व विभाग और जिलों के प्रशासनिक प्रमुखों के रूप में कलेक्टरों की सामूहिक शक्ति से सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए कार्यमंत्र को हम गुजरात में सफलतापूर्वक साकार करें।

राजस्व विभाग द्वारा अडालज स्थित त्रिमंदिर परिसर में यह तीन दिवसीय चिंतन शिविर कोलोबरेट, इनोवेट एंड ट्रांसफॉर्म फॉर बेटर लैंड गवर्नेंस की विषय वस्तु (थीम) के साथ आयोजित हो रहा है। राज्य के जिला कलेक्टर तथा राजस्व विभाग के अधिकारी इस चिंतन शिविर में सहभागी हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सदैव लोगों की सुख-सुविधा तथा लोकहित के कार्य करने की व्यवस्थाएँ विकसित कर देश का गौरव बढ़ाया है।

उन्होंने जोड़ा कि कलेक्टरों के पास विशाल अधिकार हैं और हम लोक कल्याण के कार्यों के लिए ही बैठे हैं, तब चिंतामुक्त रहकर स्पष्टता एवं संवेदना के साथ समस्याओं का हल हो; यही हमारा दायित्व होना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राजस्व अधिकारियों को उनके पास आने वाले लोगों को कोई हिचक न रहे तथा संतोष की अनुभूति हो; ऐसा आचरण-व्यवहार हँसते चेहरे से करने की भी सीख दी। इस संबंध नें श्री पटेल ने दादा भगवान के बोध को उद्धृत करते हुए कहा कि दुनिया किस प्रकार चलती है; यह समझ हमें विकसित करनी होगी और सब मैं ही करता हूँ; यह आत्ममुग्धता भाव त्यागकर सबको साथ मिलकर काम करने के रुख से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है।

मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास में राजस्व विभाग तथा जिला कलेक्टरों के योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए जीरो टोलरेंस की दिशा में सब साथ मिलकर सामूहिक चिंतन-मंथन से कार्यरत रहें।

मुख्यमंत्री ने शिविरार्थियों का प्रेरक आह्वान किया कि वे विकसित भारत-2047 के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए संकल्प को विकसित गुजरात से साकार करने के लिए पूर्णतः कार्यनिष्ठा एवं जनसेवा की प्रतिबद्धता के साथ सेवारत रहें। चिंतन शिविर के शुभारंभ अवसर पर पूज्य श्री दीपकभाई देसाई ने राज्य सरकार के राजस्व अधिकारियों-कर्मचारियों को कर्म एवं सेवा के साथ अध्यात्म को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने वाला प्रेरणादायी प्रवचन किया।

अध्यात्म, व्यवहार तथा आचार-विचार के विषय में पूज्य श्री दीपकभाई ने अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि कर्म के सिद्धांतों तथा उसके उद्देश्य को जानकर दादा भगवान द्वारा दिए गए विचारों जैसे कि चोरी न करना, सेवा भक्ति के मार्ग पर चलना, परोपकार करना, दान करना, शुद्ध आचरण, कर्म को समझना, स्व-कर्म को समझकर व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना तथा धर्म एवं संस्कार से युक्त मार्ग पर चलना अत्यंत ही आवश्यक है। उन्होंने सामान्य जीवन में महत्व रखने वाले आर्थिक व्यवहार-लेन-देन के बारे में नीति से लक्ष्मी प्राप्त करने, माता-पिता के साथ सद्व्यवहार, किसी को भी लेशमात्र हानि या दुःख न पहुँचाने वाला व्यवहार करने तथा क्रोध, लोभ माया से मुक्त होने और पूर्व जन्म के कर्म एवं जन्म-मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के उद्देश्य के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सदैव लोगों के सुख-समृद्धि एवं कल्याण तथा लोकहित कार्यों से देश का गौरव बढ़ाया है

▸▸ हम जनोन्मुखी कार्य करने ही बैठे हैं, तब चिंतामुक्त होकर स्पष्टता एवं संवेदना के साथ कार्यरत रहें

▸▸ सामूहिक शक्ति से सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के प्रधानमंत्री के कार्यमंत्र को 'विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात' से साकार करें

राजस्व राज्य मंत्री श्री संजयसिंह महीडा ने कहा कि प्रशासनिक प्रक्रिया को नागरिकों की सेवा मानकर सुदूरवर्ती व्यक्ति की समस्याएँ हल करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। गुजरात सरकार ने आईओआरए तथा ई-धरा जैसे माध्यमों द्वारा फेसलेस एवं पेपरलेस गवर्नेंस अपनाकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया है। उद्योगों एवं सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन में जीरो डीले की नीति तथा पारदर्शी प्रशासन के कारण गुजरात आज वैश्विक निवेशकों के लिए पसंदीदा राज्य बना है।

उन्होंने आगे कहा कि पूर्व में री-सर्वे में हुई क्षतियाँ सुधारने के लिए अब ड्रोन टेक्नोलॉजी तथा सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग किया जा रहा है। 135-डी के नोटिस, उत्तराधिकार तथा अधिकार पत्रक की प्रक्रियाओं को और सरल तथा तेज बनाया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जीरो टोलरेंस नीति के विजन के साथ भूमि रिकॉर्ड्स का रियल टाइम अपटेड और पूर्णतः डिजिटलाइजेशन कर पुराने कानूनों में आधुनिक सुधारों से गुजरात को अधिक उन्नत बनाया गया है।

मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार दास ने राजस्व प्रशासन के कार्य की प्रशंसा करते हुए विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए टेक्नोलॉजी तथा पारदर्शिता अपनाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में राजस्व विभाग ने विकास परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन कार्य में रिकॉर्डब्रेक प्रदर्शन किया है। विशेषकर रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी तथा सोलर सेक्टर में गुजरात आज देश में अग्रसर है और इसके मूल में राजस्व विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है। श्री दास ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए जिलों में अपर कलेक्टरों की नई रिक्तियाँ मंजूर की हैं। इसके अलावा राजस्व प्रशासन के आधारभूत ढाँचे को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पटवारी एवं सर्वेयर की नई भर्ती भी की गई है।

राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि ने चिंतन शिविर के समग्र आयोजन की विस्तृत भूमिका देते हुए कहा कि प्रशासन में केवल लॉजिक या विज्ञान ही नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन एवं आध्यात्मिक ऊर्जा का समन्वय भी अनिवार्य है। दादा भगवान के सान्निध्य में यह शिविर आयोजित करने का उद्देश्य यही है कि अधिकारी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ अपने कर्तव्य को एक 'योग' समझकर काम करें, जिससे किसी भी चुनौती के बीच भी काम करने की अपार शक्ति प्राप्त हो।

भारत में कलेक्टर संस्थान के 254 वर्षों के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आज भी जनमानस में कलेक्टर की एक विशिष्ट पहचान है। नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में यह चिंतन शिविर आयोजित करने के पीछे कारण प्रशासन में अधिक सटीकता एवं पारदर्शिता लाना है। यह शिविर केवल चर्चा तक सीमित न रहते हुए राजस्व विभाग में एक गुणात्मक परिवर्तन लाएगा, जिसका सीधा लाभ राज्य के नागरिकों को मिलेगा।

शिविर के आरंभ में राज्य के सैटलमेंट आयुक्त श्री बीजल शाह ने सभी का स्वागत करते हुए शिविर के दौरान आयोजित होने वाले विभिन्न सत्रों एवं गतिविधियों का विवरण दिया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, राहत आयुक्त एवं सचिव श्री आलोक कुमार पांडे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य श्री दिनेश कुमार असवाल, गांधीनगर जिला कलेक्टर श्री रविन्द्र खटाले सहित जिला कलेक्टर, राजस्व अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित रहे।

गुजरात सरकार की i-Hub पहल का कमाल : उद्यमी बन रहे हैं समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम

▸▸ आग बुझाने के इकोफ्रेंड्ली सॉल्यूशन 'अचूक' को मिला गुजरात सरकार का सहयोग

▸▸ आई-हब की सहायता से अहमदाबाद की महिला उद्यमी ने बच्चों को फास्टफूड से सुपरफूड की ओर मोड़ा

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई दिशा दी है। उनके विजन का अनुकरण करके गुजरात आज उद्यमिता के सुदृढ़ केन्द्र के रूप में उभर कर आया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात आज पाँचवीं बार स्टार्टअप रैंकिंग में अग्रसर बना है, जो इस क्षेत्र में हुए सुव्यवस्थित प्रयासों को दर्शाता है। राज्य में गुजरात स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन हब (i-Hub) द्वारा इनोवेशन को निरंतर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। स्टार्टअप्स को वित्तीय, ढाँचा, टेक्निकल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तथा नियमनकारी सहायता प्रदान किए जाते हैं; जिसके परिणामस्वरूप ये स्टार्टअप्स आज समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बन रहे हैं।

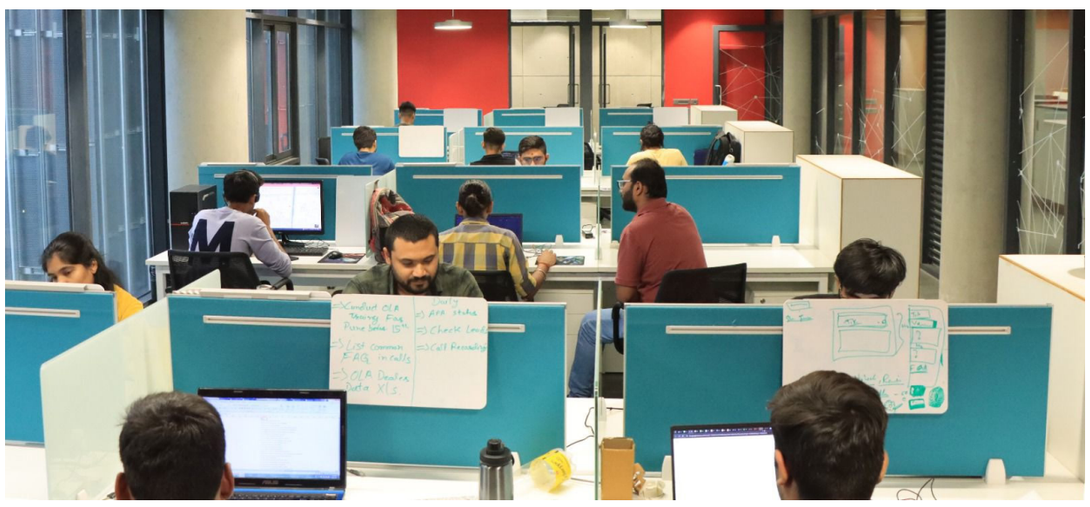

आग बुझाने के इकोफ्रेंड्ली सॉल्यूशन 'अचूक' को मिला आई-हब का सहयोग

आग लगने की बढ़ती घटनाओं के बीच जान-माल के साथ पर्यावरण की रक्षा करना एक बड़ी चुनौती बन रहा है। अहमदाबाद स्थित राहुल शाह तथा उनकी टीम ने इस चुनौती को ध्यान में रखकर आग बुझाने के इकोफ्रेंड्ली सॉल्यूशन 'Achuk एन्वायर्नमेंटल सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड' विकसित किया है। आधुनिक समय में नायलॉन तथा पीवीसी जैसे सिंथेटिक मटेरियल के बढ़ते उपयोग के कारण आग अधिक तेजी से फैलती है और बचाव के लिए बहुत कम समय रहता है। ऐसी स्थिति में 'अचूक' का सॉल्यूशन परंपरागत अग्निशामक साधनों (उपकरणों) की तुलना में अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। पानी के साथ मिश्रित होने में सक्षम यह टेक्नोलॉजी कार्बन उत्सर्जन घटाती है, पानी का बचाव करती है और पर्यावरण प्रदूषण कम करती है।

'अचूक' के संस्थापक श्री राहुल शाह ने कहा, "गुजरात सरकार के सहयोग से हमारे स्टार्टअप को प्रारंभिक चरण से ही सुदृढ़ सपोर्ट मिला है। सीड स्टार्टअप फंड अंतर्गत प्राप्त सहायता से प्रोडक्ट के अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन मिला है तथा इनक्यूबेशन सपोर्ट द्वारा मार्गदर्शन, पेटेंट, पंजीकरण प्रक्रिया और एग्जीबिशन में भाग लेने के अवसर प्राप्त हुए। आई-हब अंतर्गत प्राप्त हुए सहयोग के कारण आज हमारा स्टार्टअप सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है।"

आई-हब की सहायता से अहमदाबाद की महिला उद्यमी ने बच्चों को फास्टफूड से सुपरफूड की ओर मोड़ा

आज की फास्ट लाइफ में जब फास्टफूड का प्रभाव बढ़ रहा है, तब उसके समक्ष कोई स्वास्थ्यप्रद विकल्प मिले, तो ? अहमदाबाद की डॉ. डिंपल गणात्रा का यह विचार आज आई-हब के सपोर्ट से एक फुल फ्लेज्ड स्टार्टअप में परिवर्तित हुआ है। दो दशक से भी अधिक समय तक सर्जन के रूप में सेवा देने वालीं डॉ. डिंपल गणात्रा ने अनुचित जीवनशैली तथा फास्टफूड के कारण होने वाले रोगों एवं बच्चों में पोषण के अभाव को ध्यान में रखकर वर्ष 2022 में 'HealthyGrabz' की शुरुआत की थी। हेल्दीग्रैब्ज की विशेषता यह है कि वह भिन्न-भिन्न सब्जियों के मूल पोषण मूल्यों को बनाए रखते हुए उनसे चिप्स बनाता है।

गुजरात सरकार का आभार व्यक्त करते हुए डॉ. डिंपलबेन ने कहा, "आई-हब जैसा इनक्यूबेशन सपोर्ट सिस्टम केवल मार्गदर्शन ही नहीं; बल्कि स्टार्टअप को नेटवर्किंग, डीलर के साथ कनेक्टिविटी एवं व्यावसायिक चुनौतियों के निवारण के लिए एक सुदृढ़ प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है। किसी भी समस्या या दिक्कत के समय उचित मार्गदर्शन आसानी से मिलता है, जो उद्यमियों को आत्मविश्वास प्रदान करता है। विशेषकर महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने में राज्य सरकार का सकारात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट दिखाई देता है।"

गुजरात सरकार के समर्थन से सर्बोटेक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड को मिली नई दिशा

आणंद स्थित सर्बोटेक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा स्टार्टअप है, जिसने परंपरागत ब्रेन डेवलपमेंट पद्धतियों को आधुनिक न्यूरोकॉग्निटिव टेक्नोलॉजी के साथ एकीकृत कर अनूठा उत्पाद विकसित किया है। यह उत्पाद विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन कर उनकी ब्रेन ट्रेनिंग को अधिक प्रभावशाली बनाता है।

श्वेता प्रजापति ने अपने स्टार्टअप की सफलता का श्रेय गुजरात सरकार को देते हुए कहा, "हाल में हमारा स्टार्टअप लगभग 500 विद्यार्थियों पर अनुसंधान कर रहा है। सर्बोटेक के उपकरणों से विद्यार्थियों की मनोस्थिति का विश्लेषण हो सकता है, जिससे उनके स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। मैंने कई स्टार्टअप्स को फंडिंग तथा सपोर्ट के अभाव में विफल होते देखा है, परंतु आई-हब जैसे प्लेटफॉर्म के सहयोग से हमारा स्टार्टअप आज समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बन रहा है।"

आई-हब द्वारा लगभग 720 स्टार्टअप्स को सीधी सहायता मिली, 4000 कुशल रोजगार का सृजन हुआ

गुजरात में स्टार्टअप तथा नवाचार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अहमदाबाद में गुजरात स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन हब (आई-हब) की स्थापन की गई थी। आज यह पहल राज्य में नवाचार, रोजगार एवं उद्यमिता को वेग देने वाला सशक्त प्लेटफॉर्म बन गई है। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थापित इस अत्याधुनिक परिसर में लगभग 500 स्टार्टअप्स के एक साथ काम कर सकने की व्यवस्था है।

उल्लेखनीय है कि आई-हब द्वारा अब तक लगभग 720 स्टार्टअप्स को सीधी सहायता दी गई है और स्टार्टअप सृजन सीड सपोर्ट योजनांतर्गत 466 स्टार्टअप्स को 28 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मंजूर की गई है। आई-हब के इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स द्वारा राज्य में लगभग 4000 कुशल रोजगार का सृजन हुआ है और इन स्टार्टअप्स की कुल मार्केट वैल्यू लगभग 3569 करोड़ रुपए तक पहुँची है, जो राज्य के सशक्त स्टार्टअप इकोसिस्टम को दर्शाती है।

धूप से पैरों पर आ गए चप्पल के निशान तो घरेलू उपाय कारगर होंगे-शहनाज़ हुसैन

गर्मियों का मौसम अपने साथ जहां धूप, तपिश और उमस लेकर आता है, वहीं यह हमारी त्वचा के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है। खासतौर पर पैरों की त्वचा, जो अक्सर सैंडल या चप्पल पहनने की वजह से खुली रहती है, इस मौसम में सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। तेज धूप के सीधे संपर्क में आने से त्वचा का रंग झुलसने लगता है और पैरों पर चप्पल के डिजाइन जैसे निशान उभर आते हैं। यह स्थिति देखने में न केवल असमान लगती है, बल्कि कई बार आत्मविश्वास को भी प्रभावित करती है।

प्रख्यात सौंदर्य विशेषज्ञ शहनाज़ हुसैन के अनुसार, इस समस्या से निपटने के लिए महंगे सैलून ट्रीटमेंट ही एकमात्र विकल्प नहीं हैं। घर में मौजूद साधारण सामग्री से भी आप अपने पैरों की खोई हुई चमक और कोमलता वापस पा सकते हैं। जरूरी है तो बस थोड़ी नियमितता और सही देखभाल की समझ।

गर्मी के दिनों में धूल, मिट्टी और पसीने का असर पैरों पर जल्दी दिखने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कई दिनों से पैरों की सफाई नहीं की गई हो और उन पर मैल जम गई हो। ऐसे में सबसे पहला और जरूरी कदम है—सही तरीके से सफाई। स्क्रबिंग इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा है, जो त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाकर नई त्वचा को उभरने का मौका देता है।

घरेलू स्क्रब के रूप में टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा और नींबू का मिश्रण काफी प्रभावी माना जाता है। बेकिंग सोडा त्वचा को एक्सफोलिएट करता है, जबकि नींबू में मौजूद विटामिन C त्वचा की रंगत को निखारने में मदद करता है। इस मिश्रण को पैरों पर लगाकर हल्के हाथों से स्क्रब करने से टैनिंग धीरे-धीरे कम होने लगती है। नींबू के छिलके से स्क्रब करना भी एक अच्छा उपाय है, क्योंकि इससे त्वचा की गहराई से सफाई होती है।

इसी तरह, कॉफी और शहद का मिश्रण भी एक बेहतरीन प्राकृतिक स्क्रब के रूप में काम करता है। कॉफी के कण त्वचा की सफाई करते हैं और शहद उसे नमी प्रदान करता है। यह संयोजन पैरों को न केवल साफ करता है, बल्कि उन्हें मुलायम और चमकदार भी बनाता है।

नींबू और खीरे का मिश्रण त्वचा को ठंडक और ताजगी देने के लिए जाना जाता है। खीरे का रस त्वचा को सुकून देता है, जबकि नींबू टैनिंग को हल्का करने में मदद करता है। इस मिश्रण को कॉटन से पैरों पर लगाकर कुछ समय बाद धो लेने से त्वचा में धीरे-धीरे सुधार दिखाई देने लगता है।

घरेलू मास्क भी इस समस्या का प्रभावी समाधान हैं। आलू का रस, दही, बेसन, नींबू और शहद मिलाकर बनाया गया पेस्ट एक संपूर्ण स्किन ट्रीटमेंट का काम करता है। आलू त्वचा को हल्का करता है, दही में मौजूद लैक्टिक एसिड मृत त्वचा को हटाता है, और शहद त्वचा को हाइड्रेट करता है। इस मास्क को पैरों पर लगाकर हल्के-हल्के रगड़ते हुए हटाने से त्वचा साफ और कोमल बनती है।

बेसन और दही का उपयोग भारतीय घरों में लंबे समय से सौंदर्य के लिए किया जाता रहा है। यह मिश्रण त्वचा को साफ करने और टैनिंग हटाने में बेहद असरदार है। इसमें नींबू का रस मिलाने से इसका प्रभाव और बढ़ जाता है।

एक और खास घरेलू उपाय है टैन रिमूविंग पेस्ट, जिसमें इनो, नींबू का रस, नारियल तेल, शैंपू, कॉफी और आटा मिलाया जाता है। यह मिश्रण त्वचा की गहराई से सफाई करता है और टैनिंग को कम करने में मदद करता है। इसे हल्के हाथों से रगड़ने पर अच्छे परिणाम मिलते हैं।

लेकिन इन सभी उपायों के साथ सबसे जरूरी है—मॉइस्चराइजेशन। दिनभर धूप और धूल में रहने के बाद पैरों को गुनगुने पानी से धोना और फिर उन्हें अच्छी तरह सुखाकर मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है। रात को सोने से पहले पैरों को मॉइस्चराइज करने से त्वचा नरम और स्वस्थ बनी रहती है।

संतरे के छिलके का पाउडर और कच्चा दूध भी टैनिंग हटाने में मददगार होते हैं। संतरे में मौजूद विटामिन C त्वचा को निखारता है और इसके छिलके के कण त्वचा की सफाई करते हैं। चावल का आटा मिलाने से यह मिश्रण और प्रभावी हो जाता है।

यह सभी उपाय हमें यह सिखाते हैं कि सुंदरता के लिए महंगे उत्पादों की जरूरत नहीं होती। हमारी रसोई में ही ऐसे कई तत्व मौजूद हैं, जो हमारी त्वचा को

देश की स्थिति: बेरोजगारी, प्रदूषण, गांवों की उपेक्षा और प्राकृतिक आपदाओं को लेकर चिंताएं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। आज देश की हालत ऐसी है कि "दुल्हा-दुल्हन की मृत्यु हो जाए तो भी देश कचरे के ढेर में बदल जाएगा", "देश गड्ढे में गिरता जा रहा है, नीतियां वही रहेंगी", "अपना काम खत्म होने पर जनता किराए का बोझ उठाएगी", "नेता धन और पद के पीछे पागल हैं?" ऐसा देश पहले कभी नहीं देखा गया। ये सब पतन के लक्षण हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, देश एक भयानक संकट में है। देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, लाखों लोगों को दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है।

गांवों में समान शिक्षा नहीं है, न ही चिकित्सा सुविधाएं हैं, न ही परिवहन सुविधाएं हैं, सब कुछ शहरों में उपलब्ध है। शासक शहरों के प्रति पक्षपाती हैं। गांवों के शासकों को कोई परवाह नहीं है। शहरों में छोटे-बड़े उद्योग फल-फूल रहे हैं, वे बहुत अधिक पानी का उपयोग करते हैं और लोग पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। साथ ही, उद्योगों का अपशिष्ट जल नदियों और झीलों में बहाया जाता है। यही कारण है कि उनका पानी पीने योग्य नहीं रह गया है। वाहनों और उद्योगों के धुएं के कारण स्वच्छ हवा दुर्लभ हो गई है। क्या शहरों में प्रदूषण बढ़ गया है? और इन सबका असर वातावरण पर पड़ रहा है। यानी, अत्यधिक गर्मी, सर्दी, बारिश या तूफान की मात्रा बढ़ गई है। जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि के लिए भी हानिकारक है।

रासायनिक उर्वरकों और दवाओं ने गाँव की ज़मीन को बर्बाद कर दिया है। मिट्टी के पोषक तत्व सोख लिए गए हैं। उर्वरकों की खपत बढ़ गई है। उर्वरक और दवाएँ महँगी हो गई हैं। फसलों में कीटों को नियंत्रित करने के लिए अधिक दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है। क्या जहरीली दवाएँ हवा को प्रदूषित करती हैं, मिट्टी को खराब करती हैं और लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुँचाती हैं? क्या यह जहर बारिश के पानी के साथ बहकर नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है और समुद्र में मछलियाँ आदि नष्ट हो जाती हैं? अन्य जानवर और पक्षी भी मर रहे हैं। क्या जहर हर जगह फैल रहा है? क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले घोंघे और इल्लियाँ गायब होने लगे हैं?

प्रकृति का चक्र टूट रहा है। कृषि में ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए बैलों की संख्या कम होती जा रही है। देश सुधार के पथ पर चलकर विनाश की ओर बढ़ रहा है। और विकास के नाम पर विदेशी कर्ज के पहाड़ कम होते जा रहे हैं। कहते हैं, मेरा भारत महान है।

देश की वास्तविकता: संविधान, धर्मनिरपेक्षता और नकारात्मक राजनीति को लेकर चिंता

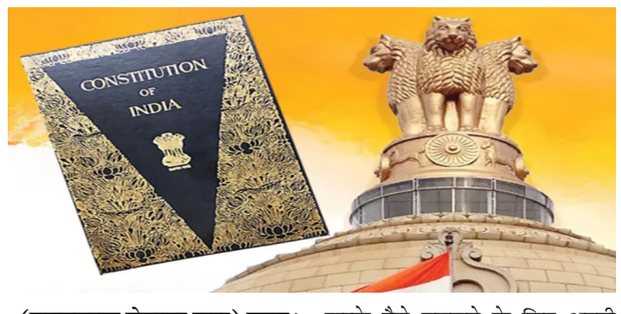

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। हमारे देश की सच्चाई यह है कि भारत का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष है और देश के सभी नागरिकों को संविधान का पालन करना चाहिए जो इस संस्कृति की रक्षा करता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर भारत को एकजुट करने और संविधान की रक्षा करने के आंदोलन में शामिल हों और नकारात्मक तत्वों को करारा जवाब देकर सच्ची भाईचारे की भावना का संदेश दें।

कुछ समय पहले कांग्रेस के राजनीतिक अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ने आपा खोकर गुजरात के लोगों को अनपढ़ और मूर्ख कहा था। हाल ही में स्वायत्त निकायों के चुनावों के नतीजों से परेशान होकर गुजरात भाजपा के अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने आपा खो दिया और कांग्रेस की लोकप्रिय महिला सांसद श्रीमती जेनीबेन ठाकोर का सार्वजनिक रूप से अपमान किया। हमारे लोकतांत्रिक देश में चुनावों में जीत और हार होना स्वाभाविक है। लेकिन इस पर किसी को भी आपा नहीं खोना चाहिए।

राजनीति में शामिल व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में कैसा होना चाहिए? यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसका जीवन खुली किताब की तरह होना चाहिए। इसके विपरीत, आजकल कुछ बेरोजगार और निकम्मे लोग चुनाव के दौरान ब्लैकमेल करके पैसे वसूलने के लिए अपनी "दुकानें" खोल लेते हैं। क्या किसी खास समुदाय को निशाना बनाकर बेमतलब और बढ़ा-चढ़ाकर भाषण देने वाले लोग कभी नगर पालिका या नगर परिषद जीत सकते हैं? क्या वे सरकार बनाने के लिए जरूरी विधायक या सांसद चुन सकते हैं? ऐसे अदूरदर्शी और निकम्मे लोगों की वजह से आज चुनाव एक चटनी बन गए हैं। और वे जो भी मिलता है उसे चाटने बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसी चटनी का स्वाद उतना स्वादिष्ट नहीं होता जितना होना चाहिए। जो जनता (मतदाताओं) को कभी पसंद नहीं आएगा।

यह देश धर्मनिरपेक्ष है और जब भी धर्मनिरपेक्ष सरकारें सत्ता में आईं, उनका लाभ, विशेष रूप से ईसाई, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी और दबे-कुचले वर्गों जैसे विभिन्न धर्मों के लोगों को मिला। देश में नफरत भरे भाषण नहीं हुए। किसी पर भी अदालत या पुलिस में गलत मुकदमा नहीं चलाया गया, लोगों को बोलने, लिखने और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने का अधिकार था, जिसमें आंदोलन भी शामिल थे। धर्मनिरपेक्ष सरकारों ने इन अधिकारों का बखूबी पालन किया और लोकतंत्र को जीवित रखा। क्या आज की नकारात्मक राजनीति देश को डुबा देगी?

भीषण गर्मी में यात्रियों को राहत: भावनगर मंडल के बोटाद स्टेशन पर निःशुल्क छाछ एवं शीतल पेयजल का वितरण

भीषण गर्मी एवं बढ़ते तापमान के मद्देनज़र यात्रियों को राहत प्रदान करने हेतु पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा जनहित में विशेष पहल की गई है। इस क्रम में दिनांक 05 मई, 2026 (मंगलवार) को बोटाद रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए निःशुल्क छाछ एवं शीतल पेयजल वितरण की व्यवस्था की गई।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि बोटाद रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म क्षेत्र में यात्रियों विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों,

महिलाओं एवं बच्चों को छाछ एवं ठंडा पेयजल उपलब्ध कराया गया, जिससे उन्हें भीषण गर्मी से काफी राहत मिली।

निःशुल्क छाछ वितरण सेवा में "माँ महावीर ग्रुप-बोटाद" का सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ। इसी प्रकार यात्रियों के लिए निःशुल्क शीतल पेयजल वितरण में "जायन्ट्स ग्रुप ओफ बोटाद" का सहयोग रहा। "माँ महावीर ग्रुप-बोटाद" ने यात्रियों के लिए निःशुल्क 100 लीटर छाछ की व्यवस्था की तथा "जायन्ट्स ग्रुप ओफ बोटाद" ने यात्रियों हेतु 400 लीटर ठंडा पानी की व्यवस्था की।

स्टेशन पर इन व्यवस्थाओं को सफलतापूर्वक संचालित करने में भावनगर मंडल के वाणिज्य विभाग के निरीक्षकों, टिकट चेकिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई तथा वितरण कार्य को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न किया।

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक (DRM) श्री दिनेश वर्मा ने कहा, "भीषण गर्मी के दौरान यात्रियों को राहत प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भावनगर मंडल द्वारा विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से इस प्रकार की जनहितकारी गतिविधियाँ निरंतर आयोजित की जा रही हैं। यह पहल हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता एवं यात्री-हित के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है।"

भावनगर मंडल द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं मानवीय सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती रहें। भीषण गर्मी के दौरान इस प्रकार की राहत सेवाएँ आगे भी निरंतर जारी रहेंगी।

क्रूड ऑयल वायदा 146 रुपये फिसला: सोना वायदा में 458 रुपये और चांदी वायदा में 1417 रुपये की वृद्धि

मुंबई: देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 117369.31 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 20992.12 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 96376.98 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का मई वायदा 36014 पॉइंट के स्तर पर ट्रेड हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2395.94 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 13246.78 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा 149749 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 149996 रुपये और नीचे में 149228 रुपये पर पहुंचकर, 149339 रुपये के पिछले बंद के सामने 458 रुपये या 0.31 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 149797 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-गिनी मई वायदा 251 रुपये या 0.21 फीसदी की बढ़त के साथ 120840 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-पेटल मई वायदा 32 रुपये या 0.21 फीसदी की तेजी के संग 15145 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर पहुंचा। सोना-मिनी मई वायदा 147361 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 147743 रुपये और नीचे में 147090 रुपये पर पहुंचकर, 429 रुपये या 0.29 फीसदी की तेजी के संग 147475 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-टेन मई वायदा प्रति 10 ग्राम 149861 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 150290 रुपये और नीचे में 149482 रुपये पर पहुंचकर, 149719 रुपये के पिछले बंद के सामने 345 रुपये या 0.23 फीसदी की तेजी के संग 150064 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा 238381 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 240800 रुपये और नीचे में 236001 रुपये पर पहुंचकर, 239383 रुपये के पिछले बंद के सामने 1417 रुपये या 0.59 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 240800 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इनके अलावा चांदी-मिनी जून वायदा 1834 रुपये या 0.74 फीसदी की बढ़त के साथ 249440 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 20992.12 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 96376.98 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 13246.78 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 36014 पॉइंट के स्तर पर

माइक्रो जून वायदा 1803 रुपये या 0.73 फीसदी की मजबूती के साथ 249478 रुपये प्रति किलो बोला गया।

मेटल वर्ग में 1969.50 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मई वायदा 8.75 रुपये या 0.69 फीसदी बढ़कर 1285.5 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता मई वायदा 2.65 रुपये या 0.77 फीसदी बढ़कर 345.1 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम मई वायदा 2.5 रुपये या 0.67 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 373.5 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मई वायदा 60 पैसे या 0.3 फीसदी चढ़कर 200.2 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 5774.38 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मई वायदा 9960 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 10066 रुपये और नीचे में 9840 रुपये पर पहुंचकर, 146 रुपये या 1.45 फीसदी गिरकर 9911 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मई वायदा 149 रुपये या 1.48 फीसदी गिरकर 9912 रुपये प्रति बैरल हुआ। इनके अलावा नैचुरल गैस मई वायदा सत्र के आरंभ में 272 रुपये के भाव पर खूलकर, 273.7 रुपये के दिन के उच्च और 269.4 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 274.5 रुपये के पिछले बंद के सामने 3.6 रुपये या 1.31 फीसदी गिरकर 270.9 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मई वायदा 3.7 रुपये या 1.35 फीसदी लुढ़ककर 270.9 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मई वायदा 982.2 रुपये पर खूलकर, 1.2 रुपये या 0.12 फीसदी औंधकर 986 रुपये प्रति किलो पर आ गया। कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 8405.81 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 4840.97 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 1428.84 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 255.41 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 8.74 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 268.40 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 4149.85 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1598.75 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 1.03 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 11510 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 68588 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 27813 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 379644 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 59876 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 8140 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 23350 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 82355 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 21202 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 25545 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स मई वायदा 35942 पॉइंट पर खूलकर, 36014 के उच्च और 35942 के नीचले स्तर को छूकर, 189 पॉइंट बढ़कर 36014 पॉइंट के स्तर पर ट्रेड हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मई 10000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 99.5 रुपये की गिरावट के साथ 586.6 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मई 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.6 रुपये की गिरावट के साथ 13.85 रुपये हुआ। सोना मई 170000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 20 रुपये की बढ़त के साथ 222 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 11.5 रुपये की गिरावट के साथ 591 रुपये हुआ। तांबा मई 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.73 रुपये की बढ़त के साथ 19.19 रुपये हुआ। जस्ता मई 345 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 65 पैसे के सुधार के साथ 4.4 रुपये हुआ। पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मई 9000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 14 रुपये की बढ़त के साथ 247 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मई 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.05 रुपये की बढ़त के साथ 12.15 रुपये हुआ। सोना मई 140000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 80 रुपये की गिरावट के साथ 644 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 220000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 311.5 रुपये की गिरावट के साथ 2012 रुपये हुआ। तांबा मई 1250 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 2.03 रुपये की गिरावट के साथ 12.9 रुपये हुआ। जस्ता मई 342.5 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 71 पैसे के सुधार के साथ 5.64 रुपये हुआ।